Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

अक्टूबर 2022 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- बुजुर्गों के लिये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की जाएगी सियान हेल्पलाइन 3
- राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 पर किये हस्ताक्षर 3
- राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 पर किये हस्ताक्षर 4
- स्वच्छता सर्वेक्षण की इंडियन स्वच्छता लीग (आईएसएल) में छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकाय पहले नंबर पर, एक को मिला दूसरा स्थान 4
- मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती के अवसर पर दो नए पुरस्कारों की घोषणा की 5
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर 5
- मुख्यमंत्री ने 'महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना' का किया प्रदेशव्यापी शुभारंभ 6
- बिलासपुर-इंदौर विमान सेवा का हुआ शुभारंभ 6
- राज्य अलंकरण श्रेणी में दिये जाएंगे तीन नए पुरस्कार 7
- छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोज़गारी 8
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शरुआत 9
- मुख्यमंत्री ने कांकेर में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का किया लोकार्पण 9
- मुख्यमंत्री ने नंदनवन जंगल सफारी में 10 नए बाड़ों का किया लोकार्पण 10
- मुख्यमंत्री ने धुरागाँव में स्थापित इमली प्रसंस्करण संयंत्र का किया शुभारंभ 11
- कबीरधाम ज़िले के चौथे अनुविभाग सहसपुर लोहारा का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ 11
- रायपुर में होगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई 'एग्री कार्निवल 2022' का आयोजन 12
- मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सूचना आयोग के ऑनलाईन पोर्टल का किया लोकार्पण 13
- छत्तीसगढ़ में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि 13
- 'नदी तट वृक्षारोपण' कार्यक्रम के तहत 26 नदियों के तट पर लगाए गए 15 लाख से अधिक पौधे 14
- भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नवगठित ज़िला सक्ती में मुख्यमंत्री की घोषणा 14
- पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों में पी.पी.पी. मॉडल से संचालित होंगे कॉलेज 15
- नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में नारायणपुर टॉप 5 आकांक्षी ज़िलों में शामिल 16
- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल 17
- इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ को किया गया पुरस्कृत 17
- छत्तीसगढ़ में होगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 18
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मिला राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच सिल्वर अवार्ड 18
- मुख्यमंत्री ने 28 ज़िलों में सिकलसेल प्रबंधन केंद्रों का किया उद्घाटन 19
- समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की सहूलियत के लिये एन्ड्रॉयड ऐप 'टोकन तुंहर हाथ 19

नोट :

छत्तीसगढ़

बुजुर्गों के लिये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की जाएगी सियान हेल्पलाइन

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदेश में बुजुर्गों के लिये एक नवंबर (राज्य निर्माण दिवस) से सियान हेल्पलाइन प्रारंभ करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- यह हेल्पलाइन ऐसे वृद्धजन, जिनकी संतानें विदेश या देश के अन्य स्थानों में कार्यरत् हैं, को आपात् स्थितियों में सहायता पहुँचाने में मदद करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर पुलिस और समाज कल्याण विभाग से चर्चा कर हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा है।
- ऐसे वृद्धजन, जो घर में अकेले हों और जिनकी संतानें प्रदेश के बाहर कार्यरत् हैं, के लिये आपात् स्थितियों में सहायता हेतु प्रदेश में कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ सियान हेल्पलाइन शुरू करने की पहल की है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज में सम्मानजनक वातावरण, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, चिकित्सकीय देखभाल, आश्रय प्रदान करने तथा विधिक सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबंध किये गए हैं। 'मुख्यमंत्री पेंशन योजना' और 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' के माध्यम से बुजुर्गों को पेंशन राशि प्रदान की जा रही है।
- निराश्रित बुजुर्गों को नि:शुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा तथा पारिवारिक वातावरण प्रदान करने के लिये प्रदेश के 23 ज़िलों में 31 वृद्धाश्रम संचालित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम एक वृद्धाश्रम संचालित हो, ताकि निराश्रित बुजुर्गों को आश्रय मिल सके।
- मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ऐसे बुजुर्ग, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या वृद्धावस्था के कारण दैनिक क्रियाकलाप के लिये पूरी तरह दूसरों पर आश्रित हैं, उनकी चिकित्सा और देखरेख के लिये कबीरधाम, दुर्ग एवं बालोद ज़िले में प्रशामक देखरेख गृह शुरू किये गए हैं।
- बुजुर्गों को वृद्धावस्था में होने वाली समस्या के निराकरण हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण, चिकित्सीय देखभाल की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से बुजुर्गों को वाकर, बैसाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र जैसे उपकरण प्रदान किये जाते हैं।

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 पर किये हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर किये। इस संशोधन में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिये वर्तमान में प्रभावशील ऊर्जा प्रभार के शुल्क की दरों में प्रतिशत में वृद्धि की गई है।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक के भाग क (धारा 3(1) (अ)) में उल्लेखित सरल क्र. 1 व 2 में क्रमश: घरेलू उपभोक्ताओं के लिये वर्तमान ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में प्रभावशील शुल्क की दर 8 प्रतिशत में 3 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 11 प्रतिशत तथा गैर-घरेलू उपभोक्ता के लिये वर्तमान प्रभावशील दर 12 प्रतिशत में 5 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 17 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया है।
- इसी प्रकार भाग क (धारा 3(1) (अ)) में सरल क्र.3 से 13 के विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी तथा औद्योगिक इकाईयों, लघु व मध्यम उद्योगों आदि के लिये शुल्क वृद्धि की गई है। सरल क्र.14 व 15 के लिये अनुसूची की उच्चतम दर निर्धारित की गई है।

नोट :

- इसी प्रकार भाग ख की धारा 3 (1) (ब) में सरल क्र. 16 के उपभोक्ता, अर्थात् राज्य के बाहर खुली पहुँच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत उपभोग के लिये शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- विधेयक के भाग-ग (धारा 3 (1) (स)) के सरल क्र. 17, 19, 20, 21, 22 और 24 में उल्लेखित उत्पादन कंपनियों, राज्य की निजी व सार्वजनिक कंपनियाँ आदि इकाईयों के लिये ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें बढ़ाई गई हैं तथा सरल क्र. 18 में उल्लेखित उत्पादन इकाईयों के लिये शुल्क यथावत रखा गया है।

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 पर किये हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर किये। इस संशोधन में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिये वर्तमान में प्रभावशील ऊर्जा प्रभार के शुल्क की दरों में प्रतिशत में वृद्धि की गई है।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक के भाग क (धारा 3(1) (अ)) में उल्लेखित सरल क्र. 1 व 2 में क्रमश: घरेलू उपभोक्ताओं के लिये वर्तमान ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में प्रभावशील शुल्क की दर 8 प्रतिशत में 3 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 11 प्रतिशत तथा गैर-घरेलू उपभोक्ता के लिये वर्तमान प्रभावशील दर 12 प्रतिशत में 5 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 17 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया है।
- इसी प्रकार भाग क (धारा 3(1) (अ)) में सरल क्र.3 से 13 के विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी तथा औद्योगिक इकाईयों, लघु व मध्यम उद्योगों आदि के लिये शुल्क वृद्धि की गई है। सरल क्र.14 व 15 के लिये अनुसूची की उच्चतम दर निर्धारित की गई है।
- इसी प्रकार भाग ख की धारा 3 (1) (ब) में सरल क्र. 16 के उपभोक्ता, अर्थात् राज्य के बाहर खुली पहुँच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत उपभोग के लिये शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- विधेयक के भाग-ग (धारा 3 (1) (स)) के सरल क्र. 17, 19, 20, 21, 22 और 24 में उल्लेखित उत्पादन कंपनियों, राज्य की निजी व सार्वजनिक कंपनियाँ आदि इकाईयों के लिये ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें बढ़ाई गई हैं तथा सरल क्र. 18 में उल्लेखित उत्पादन इकाईयों के लिये शुल्क यथावत रखा गया है।

स्वच्छता सर्वेक्षण की इंडियन स्वच्छता लीग (आईएसएल) में छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकाय पहले नंबर पर, एक को मिला दूसरा स्थान

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2022 को स्वच्छता सर्वेक्षण की इंडियन स्वच्छता लीग (आईएसएल) में विजयी शहरों का ऐलान किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकाय पहले नंबर पर और एक दूसरे स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का पुरस्कार वितरण समारोह 1 अक्टूबर, 2022 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति एवं केंद्रीय मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। पुरस्कारों की विस्तृत घोषणा अभी तक भारत सरकार द्वारा नहीं की गई है। पुरस्कारों के विवरण राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार डेशबोर्ड के उद्घाटन उपरांत प्राप्त होंगे।
- इंडियन स्वच्छता लीग में अलग-अलग वर्गों के तहत 15 हज़ार से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में भटगांव और माना कैंप, 15 से 25 हज़ार की आबादी में खैरागढ़, 25 से 50 हज़ार की आबादी वाले निकाय में जशपुर नगर और कोंडागांव, 50 हज़ार से 1 लाख में बिरगांव, 1 लाख से 3 लाख की आबादी में अंबिकापुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किये हैं, वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

नोट :

- स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 हेतु राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों ने भाग लिया है। इस हेतु विगत 8 माह से लगातार सर्वे की टीम निकायों के भ्रमण पर रही था। सर्वे की टीम द्वारा निकायों में मिशन क्लीन सिटी, स्वच्छता श्रृंगार, सुविधा 24, गोधन न्याय योजना, निदान-1100, निष्ठा आदि राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का निरीक्षण किया गया। निकायों के निरीक्षण उपरांत ओडीएफ की स्थिति पूर्व वर्षों की तरह ही अच्छी पाई गई।
- इस बार के आयोजित समारोह में देश में सबसे अधिक निकाय छत्तीसगढ़ के ही ओडीएफ होने की उम्मीद है।
- राज्य शासन द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित जन-जागरण प्रतिनिधियों, जैसे- महापुरुषों की प्रतिमाओं की नागरिकों द्वारा साफ-सफाई, चौराहों की ब्रांडिंग, स्मारकों का रख-रखाव आदि में भी राज्य के निकायों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती के अवसर पर दो नए पुरस्कारों की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

2 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर देश के ख्याति नाम रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक स्वर्गीय हबीब तनवीर तथा साहित्यकार व पर्यावरणविद् स्वर्गीय अनुपम मिश्र के नाम से पुरस्कार पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों विभूतियों के नाम से पुरस्कार दिये जाने की यह घोषणा रायपुर के शहीद स्मारक भवन में गांधी, युवा और नए भारत की चुनौतियाँ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में की।
- गौरतलब है कि प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक स्वर्गीय हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर, 1923 को रायपुर में हुआ था। वे शिक्षा हासिल करने के बाद 1945 में मुंबई चले गये और प्रोड्यूसर के तौर पर आकाशवाणी में नौकरी शुरू की। वहाँ रहते हुए उन्होंने हिन्दी फिल्मों के लिये गाने लिखे। कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। कई नाटकों की रचना की।
- हबीब तनवीर को कई अवार्ड एवं वर्ष 2002 में पँ विभूषण सम्मान मिला। वे 1972 से 1978 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। उनका नाटक चरणदास चोर, एडिनवर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल (1982) में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। उनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार (1954), चरणदास चोर (1975) शामिल हैं।
- जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गाँधीवादी पर्यावरणविद् स्वर्गीय अनुपम मिश्र का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में सरला मिश्र और प्रसिद्ध हिन्दी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के यहाँ सन् 1948 में हुआ।
- उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1969 में संस्कृत से स्नातकोत्तर किया और इसके बाद वे दिल्ली स्थित गाँधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़ गए। पर्यावरण के लिये वह तब से काम कर रहे थे, जब से देश में पर्यावरण का कोई विभाग नहीं खुला था। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा।
- उन्हें वर्ष 2007-2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1996 में इंदिरा गाँधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर

चर्चा में क्यों ?

2 अक्टूबर, 2022 को गांधी जयंती पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में चार पुरस्कार प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- पेयजल और स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सर्वेक्षण में टॉप परफॉर्मिंग राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ ने ईस्ट जोन में बाजी मारी है। इसके साथ 3 अन्य कैटेगरी में भी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

नोट :

- ईस्ट ज़ोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में दुर्ग और बालोद ने क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
- इसके साथ ही ओडीएफ प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल ज़ोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने 'महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना' का किया प्रदेशव्यापी शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

2 अक्टूबर, 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्त्वाकांक्षी 'महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना'का प्रदेशव्यापी शुभारंभ करते हुए प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। साथ ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 'रीपा'के 'लोगो'का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ग्रामीण गरीब परिवारों के लिये रोज़गार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिये गाँव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिये यहाँ विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इन पार्कों को ग्रामीण उत्पादन एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गाँवों के सपने को साकार करने में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। इस योजना के माध्यम से गाँवों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में मज़बूती से कदम उठाया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किये जा रहे हैं। इसके लिये गौठानों में एक से तीन एकड़ भूमि पार्क के लिये आरक्षित की गई है। प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खंड में दो गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- चालू वित्तीय वर्ष के बजट में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिये 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों को एक-एक करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से इन पार्कों में वर्किंग शेड और एप्रोच रोड के निर्माण के साथ बिजली-पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।
- 'सुराजी गाँव योजना'के तहत विकसित किये गए गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि और उद्यानिकी फसलों तथा लघु वनोपजों के प्रसंस्करण की इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। साथ ही आटा-चक्की, दाल मिल, तेल मिल की स्थापना भी की जा रही है।
- इन गतिविधियों में ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं और युवाओं को रोज़गार के साथ आय के अच्छे साधन मिल रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस योजना के लिये नोडल विभाग बनाया गया है।

बिलासपुर-इंदौर विमान सेवा का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

3 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नागरिक उडन्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिलासपुर-इंदौर विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर फ्लाईट को बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा चकरभाटा बिलासपुर से रवाना किया।

नोट :

- बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर विमान सेवा सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को पूर्वाह्न 35 बजे बिलासपुर से रवाना होकर दोपहर 1.25 बजे इंदौर पहुंचेगी और इंदौर से दोपहर 1.55 बजे रवाना होकर अपराह्न 3.45 बजे बिलासपुर वापस लौटेगी।
- बिलासपुर से इंदौर रवाना हुई पहली फ्लाईट 50 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। इस मार्ग पर एलायंस एयर द्वारा 72 सीटर विमान का संचालन किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ करने और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब की स्थापना के लिये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से आग्रह करते हुए कहा कि रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार तैयार किया जा चुका है। रायपुर एयरपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाईट के संचालन के लिये तैयार है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा रायपुर एयरपोर्ट हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 20 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जिस पर रनवे विस्तार, नवीन टर्मिनल भवन निर्माण, एटीसी टॉवर निर्माण कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार तैयार किया जा चुका है। एयरपोर्ट विकास हेतु भूमि की लंबित मांग, एयरपोर्ट परिसर के सुरक्षा सबंधी समस्याओं का राज्य शासन द्वारा समाधान कर लिया गया है।
- मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से रीजनल कनेक्टिविटी योजनांतर्गत अंबिकापुर से बिलासपुर, रायपुर को जोड़ते हुए निकटवर्ती प्रमुख शहरों वाराणसी, राँची, पटना, भुवनेश्वर जैसे शहरों के लिये विमान सेवा प्रारंभ करने का आग्रह भी किया।
- मुख्यमंत्री बघेल ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिये राज्य शासन द्वारा किये गए प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का 3-C VFR श्रेणी में उन्नयन किया गया है।
- एलायंस एयर कंपनी द्वारा बिलासपुर से दिल्ली-जबलपुर-बिलासपुर-प्रयागराज वायुमार्ग पर 1 मार्च, 2021 को प्रथम नियमित घरेलू विमान सेवा प्रारंभ की गयी तथा 5 जून, 2022 से बिलासपुर से भोपाल के लिये भी नियमित विमान सेवा शुरू की गई।
- बिलासपुर एयरपोर्ट को 3- C IFR मानक अनुसार तैयार करने एवं यहाँ नाईट लैण्डिंग की सुविधा के विकास के लिये 22 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों की स्वीकृति जारी की जा रही है। एयरपोर्ट से विमानों के सुगम संचालन हेतु पीबीएन नेविगेशन प्रणाली की स्थापना के लिये भारतीय विमानपत्तन को राज्य शासन द्वारा राशि का भुगतान कर दिया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा अंबिकापुर एयरपोर्ट को 3- C VFR श्रेणी के अनुसार विकसित करने के लिये रनवे विकास व विस्तार, सिटी साईड के विकास कार्यों हेतु 00 करोड़ के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। 31 दिसंबर, 2022 तक एयरपोर्ट को विकसित कर इसके लायसेंसिंग हेतु आवेदन करने का लक्ष्य है।
- केंद्रीय नागरिक उडन्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बिलासपुर और इंदौर दोनों ही शहरों का आर्थिक और धार्मिक रूप से काफी महत्त्व है, इन दोनों शहरों के एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने पर दोनों शहरों के लोगों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी।

राज्य अलंकरण श्रेणी में दिये जाएंगे तीन नए पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

5 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लोक कला साधकों के सम्मान को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना पर दिये जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में तीन नए पुरस्कार देने की घोषणा की। यह पुरस्कार लोक कलाकार स्व. लक्ष्मण मस्तुरिया और स्व. खुमान साव तथा भगवान राम की माता कौशल्या को समर्पित होंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं जीवंत संस्कृति के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ के लयबद्ध संगीत, लोकगीत एवं लोक नाट्य अद्भुत आनंद की अनुभूति कराते हैं।
- प्रदेश की लोकगीत व लोक संगीत की महान विरासत के संरक्षण एवं संवर्द्धन और इस क्षेत्र में काम कर रहे नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राज्य अलंकरण के रूप में अन्य पुरस्कारों के साथ तीन नए पुरस्कार भी दिये जाएंगे।

नोट :

- इसमें लोकगीत के क्षेत्र में 'लक्ष्मण मस्तुरिया पुरस्कार' दिया जाएगा। वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को 'खुमान साव पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह माता कौशल्या के मायके और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण (मानस) मंडली को 'माता कौशल्या सम्मान' से अलंकृत किया जाएगा।
- राज्य अलंकरण की भाँति ही इन श्रेणियों के पुरस्कार भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रदान किये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की संस्कृति के ध्वज वाहकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके नाम पर पुरस्कार संस्थित किये जाने से उन महान कलाकारों के योगदान की जानकारी भी भावी पीढ़ी को होगी। इसके अलावा लोकगीत व लोक संगीत के प्रति रुचि भी बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोज़गारी

चर्चा में क्यों ?

4 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सितंबर में बेरोज़गारी दर अब तक अपने न्यूनतम स्तर 1 प्रतिशत है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- जनसंपर्क विभाग ने बताया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी ताजा आँकड़ों के अनुसार राज्य के 90 फीसद लोग किसी न किसी रोज़गार से जुड़कर आजीविका हासिल कर रहे हैं।
- सीएमआईई द्वारा जारी ताजा आँकड़ों के अनुसार सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर 1 फीसदी दर्ज की गई है, जबकि सितंबर माह में देश में बेरोजगारी दर का यह आँकड़ा 6.43 फीसदी रहा है। देश के शहरी क्षेत्रों में 7.70 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में सितंबर माह में बेरोज़गारी का आँकड़ा 5.84 फीसद रहा।
- सीएमआईई द्वारा 1 अक्टूबर, 2022 को बेरोज़गारी दर के संबंध में जारी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2022 में सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में 1 फीसदी के साथ छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। वहीं इसी अवधि में 0.4 फीसदी के साथ असम दूसरे स्थान पर तथा उत्तराखंड 0.5 फीसदी बेरोज़गारी दर के साथ तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में यह आँकड़ा 0.9 प्रतिशत और गुजरात में यह आँकड़ा 1.6 प्रतिशत रहा है।
- दूसरी ओर सितंबर 2022 में सर्वाधिक बेरोज़गारी दर के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है, जहाँ 8 फीसदी बेरोज़गारी दर दर्ज की गई है। जम्मू एवं कश्मीर में 23.2 फीसदी, हरियाणा में 22.9 फीसदी, त्रिपुरा में 17.0 फीसदी और झारखंड में 12.2 फीसदी बेरोज़गारी दर दर्ज की गई है।
- न्यूनतम बेरोज़गारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को मिली इस उपलब्धि के पीछे वजह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में रोज़गार के नए अवसरों के सृजन के लिये बनाई गई योजना और नीतियां रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीते पौने चार साल के भीतर अनेक ऐसे नवाचार हुए हैं, जिनसे शहर से लेकर गाँव तक हर हाथ को काम मिला है।
- छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ काम करना शुरू किया। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के साथ गाँवों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में नवाचार किये गए। इसमें 'सुराजी गाँव योजना' के अंतर्गत 'नरवा-गरूवा-घुरवा-बाड़ी' कार्यक्रम ने महती भूमिका निभाई तो दूसरी ओर 'गोधन न्याय योजना' के साथ गौठानों को रुरल इंडस्ट्रियल पार्क के तौर पर विकसित किया गया, जिससे गोबर बेचने से लेकर गोबर के उत्पाद बनाकर ग्रामीणों को रोजगार मिला। रोज़गार के नए अवसर सृजित हुए।
- 7 से बढ़ाकर 65 प्रकार के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इन लघु वनोपजों के प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन किया गया। इससे वनांचल में भी लोगों को रोज़गार मिला।
- 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' से किसानों की आर्थिक समृद्धि की दिशा में प्रयास हुए तो वहीं इस योजना के बाद उत्साहित किसानों की दिलचस्पी कृषि की ओर बढ़ी। राज्य में खेती का रकबा और उत्पादन बढ़ा।
- 'राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर योजना' के तहत 'पौनी-पसारी' व्यवस्था से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता मिली। राज्य में नई उद्योग नीति लागू की गई, जिसमें अनेक वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी के प्रावधान किए गए। इससे उद्यमिता विकास को गति मिली।

नोट :

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

6 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिये सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की जानकारी देने वाले ब्रॉशर का भी विमोचन किया।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लोगों को जोड़ कर रखने तथा स्थानीय खेलकूद को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। इससे स्थानीय लोगों को एक तरफ खेल का मंच मिलेगा, वहीं उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और खेल भावना का भी विकास होगा।
- 6 अक्टूबर से 6 जनवरी, 2023 तक चलने वाले इस ओलंपिक में दलीय एवं एकल श्रेणी में 18 वर्ष से कम, 18 से 40 वर्ष एवं 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं।
- इस ओलंपिक में दलीय एवं एकल श्रेणी में 14 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इसमें दलीय श्रेणी में गिल्ली-डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी और बांटी (कंचा) जैसे खेल शामिल किये गए हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद शामिल हैं।
- इसके अलावा इसमें वालीबॉल, हॉकी और टेनिस बॉल तथा क्रिकेट को भी शामिल किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति व सभ्यता एवं विशिष्ट पहचान यहाँ की ग्रामीण परंपराओं और रीति-रीवाजों से है। इसमें पारंपरिक खेलों का विशेष महत्त्व है। पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के इन खेलों को लोग भूलते जा रहे थे। खेलों को चिरस्थायी रखने, आने वाली पीढ़ी से इनको अवगत कराने के लिये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है।
- छत्तीसगढ़ के ये खेल मनोरंजक होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिये भी लाभदायक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन खेलों से बच्चे, बुजुर्ग व युवा सभी व्यायाम आदि शारीरिक गतिविधियों से जुड़ते हैं।
- उल्लेखनीय है कि 6 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल करते हुए इस वर्ष से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया था।

मुख्यमंत्री ने कांकेर में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

7 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर ज़िले के नाथिया नवागांव में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया। इससे कोदो-कुटकी-रागी की खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ महिला स्व-सहायता समूहों को भी फायदा मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि मिलेट मिशन के अंतर्गत स्थापित यह इकाई भारत की सबसे ज़्यादा क्षमता वाली इकाई है। इस इकाई की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10 से 12 हज़ार टन है, जिसके लिये प्रतिदिन लगभग 34 से 40 टन कोदो-कुटकी-रागी की आवश्यकता होगी।
- इस प्रसंस्करण इकाई में 7 प्रकार की मशीनों द्वारा कोदो-कुटकी-रागी को प्रसंस्कृत कर कोदो-कुटकी-रागी से चावल तथा इनका दलिया, सूजी, आटा सेंवई, पास्ता, सूप मिक्स, बिस्किट, कुकीज, लड्डू इत्यादि बनाए जाएंगे। साथ-साथ इनकी पैकेजिंग भी की जाएगी। इन उत्पादों की मार्केटिंग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी।
- उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर के बकावंड में काजू प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई है, जिससे वहां के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। लोहंडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम धुरागाँव में इमली प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई है, जिससे इमली संग्राहकों को लाभ मिलेगा।

नोट :

- छत्तीसगढ़ शासन के मिलेट मिशन के अंतर्गत स्थापित इस इकाई को प्रोत्साहन हेतु सीएसआईडीसी द्वारा सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस इकाई की स्थापना के लिये आई.आई.एम.आर. हैदराबाद के साथ अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड एवं ज़िला प्रशासन उत्तर बस्तर कांकेर के बीच तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज, सीड बैंक की स्थापना और प्रशिक्षण के लिये एमओयू किया गया है।
- अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड की प्रसंस्करण इकाई से 100 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होगा तथा ज़िले के लगभग 4 हज़ार एवं राज्य के लगभग 25 हज़ार किसान भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे, जो कोदो-कुटकी-रागी फसल की खेती करते हैं। साथ-ही-साथ उन महिला समूहों को भी लाभ मिलेगा, जो इनकी खरीदी करते हैं। इस इकाई की स्थापना से ज़िले के किसान कोदो-कुटकी-रागी की खेती के लिये प्रोत्साहित होंगे।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट के उत्पाद, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2021 से 'मिलेट मिशन' प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के 20 से अधिक ज़िलों में मिलेट्स का उत्पादन होता है।
- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 से कोदो, कुटकी एवं रागी का प्रथम बार समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय की व्यवस्था की गई। कोदो एवं कुटकी हेतु 30 रुपए प्रति किलो एवं रागी के लिये 77 रुपए प्रति किलो का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा धान के बदले अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिये राज्य शासन द्वारा 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के तहत इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है।
- मिलेट्स जैसे कि कोदो-कुटकी-रागी उच्च पौष्टिक धान्य हैं। मिलेट्स ग्लूटेन मुक्त होते हैं तथा इनमें प्रोटीन, डायट्री फाइबर, विटामिन्स और मिनरलस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मिलेट्स मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग व कई अन्य बीमारियों के लिये लाभकारी होते है तथा इनसे इम्युनिटी भी बढ़ती है।

मुख्यमंत्री ने नंदनवन जंगल सफारी में 10 नए बाड़ों का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

7 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन्यप्राणि संरक्षण सप्ताह के अवसर पर राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नवा रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी में लोगों को वन्य प्राणियों को करीब से जानने का मौका देने और उन्हें जागरूक करने के लिये 10 नए बाड़ों का लोकार्पण किया। इन्हें मिलाकर जंगल सफारी में अब कुल 28 बाड़े हो गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नंदनवन जंगल सफारी की शेरनी 'कृति' द्वारा माह मई 2021 में जन्मे तीन शावकों का नामकरण अरपा, पैरी तथा शबरी के नाम से किया।
- मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बारनवापारा अभयारण्य में पाए जाने वाली रंग-बिरंगी तितलियों की जानकारी पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया।
- मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में कहा कि अभी प्रदेश में वन्यप्राणि सप्ताह मनाया जा रहा है। वन्यप्राणियों की रक्षा करने और उनके साथ अपना साहचर्य बढ़ाने के संकल्प के साथ हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्यप्राणि सप्ताह का आयोजन किया जाता है।
- छत्तीसगढ़ वन एवं वन्यप्राणियों से समृद्ध राज्य है। प्रदेश में 44 प्रतिशत से अधिक हिस्से वनों से आच्छादित हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्यप्राणि विचरण करते हैं। राज्य सरकार द्वारा इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में वन तथा वन्यप्राणि, दोनों की ही सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा गया है।
- मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यहाँ स्थित राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैव विविधता की दृष्टि से भी समृद्ध हैं। राज्य में वन्यप्राणि संरक्षण के तहत हो रहे कार्यों के फलस्वरूप वन्यप्राणियों के भोजन तथा रहवास की सुविधा की उपलब्धता बढ़ी है। इसके अंतर्गत हाथी-मानव द्वंद्व को रोकने में भी नरवा विकास कार्यक्रम एक कारगर माध्यम बना है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वन तथा वन्य प्राणि की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा हरसंभव पहल की जा रही है। इसके तहत राज्य में वर्तमान में संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत 3 राष्ट्रीय उद्यान, 11 अभयारण्य, 3 टाईगर रिज़र्व, एक हाथी रिज़र्व और एक बायोस्फियर रिज़र्व के माध्यम से वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन के विविध कार्य किये जा रहे हैं।

नोट :

- कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर, एशिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल सफारी है। यहाँ अनेक प्रकार के वन्य प्राणियों की संख्या बहुतायत में है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) पी.वी. नरसिंग राव ने बताया कि राज्य में वन तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिये विभाग द्वारा लगातार कार्य किये जा रहे हैं। जंगल सफारी में 10 नए बाड़ों का लोकार्पण किया गया है। इनमें जंगली कुत्ते, भेड़िये, बायसन, चीतल, सांभर, चिंकारा, साही, नेवला, मसक बिलाव तथा सर्पों के बाड़े शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने धुरागाँव में स्थापित इमली प्रसंस्करण संयंत्र का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

7 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एकदिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान लोहंडीगुड़ा विकासखंड के धुरागाँव में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की संभावना बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ रोज़गार सृजन के लिये स्थानीय वनोपज और कृषि उपज का यहीं प्रसंस्करण आवश्यक है तथा यह संयंत्र इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
- संयंत्र के संचालक कार्तिक कपूर ने बताया कि इस संयंत्र में प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन इमली गूदा, 5 मीट्रिक टन इमली चपाती और 3 मीट्रिक टन इमली बीज का पाउडर बनाने की क्षमता है।
- यह संयंत्र सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ पीईबी और पफ पैनल में कुल निर्माण के 35000 वर्ग फीट के साथ 2 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ खाद्य प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही, उपकरणों के तौर पर प्रीमियम गुणवत्ता वाली स्टील का उपयोग किया गया है।
- यहाँ एफएसएसएआई के सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह संयंत्र पूरी तरह से स्वचालित है, पावर बैकअप, निर्बाध निर्माण के लिये मैनुअल मोड में काम करने का प्रावधान है।

कबीरधाम ज़िले के चौथे अनुविभाग सहसपुर लोहारा का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

10 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात में कबीरधाम ज़िले के प्रवास के दौरान विकासखंड मुख्यालय सहसपुर लोहारा में नवीन राजस्व अनुविभाग मुख्यालय कार्यालय का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में तहसील सहसपुर लोहारा को अनुविभाग का दर्जा दिया गया। इसके शुभारंभ के बाद यह ज़िले का चौथा अनुविभाग होगा।
- तहसील का भौगोलिक क्षेत्र 61479 हेक्टेयर है। इसके अंतर्गत 1 नगरीय निकाय, 96 ग्राम पंचायत, 198 गाँव शामिल हैं।
- सहसपुर में 1 स्वास्थ्य केंद्र, 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 25 उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। तहसील सहसपुर के अंतर्गत 22 धान खरीदी केंद्र, 5 राजस्व निरीक्षक मंडल और 45 पटवारी हलका हैं।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सहसपुर तहसील की जनसंख्या 152238 है, जिसमें 72792 पुरुष और 72929 महिला हैं।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम ज़िले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ज़िले को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

नोट :

- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान विकासखंड बोड़ला, विकासखंड सहसपुर लोहारा और कवर्धा नगर के लिये कई घोषणाएँ भी कीं-
  - विकासखंड बोड़ला के ग्राम झलमला में नया ग्राम पंचायत भवन बनाया जाएगा।
  - विकासखंड बोड़ला के चिल्फी, रेंगाखार और पोड़ी में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा।
  - विकासखंड सहसपुर लोहारा- 240 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु घटोला जलाशय का निर्माण कराया जायेगा।
  - विकासखंड सहसपुर लोहारा के पिपरिया में स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा।
  - कवर्धा नगर में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समाज की संस्कृति को सेहजने और संरक्षण के लिये भोरमदेव में बैगा आदिवासी समाज के संग्रहालय के निर्माण की घोषणा।

रायपुर में होगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई 'एग्री कार्निवल 2022' का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

11 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई 'एग्री कार्निवल 2022' का आयोजन 14 से 18 अक्टूबर तक किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किये जा रहे एग्री कार्निवल में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कृषि संस्थानों के निदेशक, कृषि वैज्ञानिक, विभिन्न कृषि उत्पाद निर्माता कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, स्टार्टअप्स उद्यमी एवं बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे।
- इस अवसर पर एक बृहद् अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले सह प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। एग्री कार्निवल के दौरान प्रत्येक दिन कृषकों, छात्रों एवं आम नागरिकों के लिये विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्र में उगाई जा रही फसलों एवं कृषि प्रदर्शनी का भ्रमण आयोजित किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई 'एग्री कार्निवल 2022' को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा राज्य शासन के कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ बायोटेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस, नाबार्ड, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इन्टरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), एनएबीएल तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।
- पाँच दिवसीय कृषि मड़ई के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, जिनमें कृषि उपज निर्यात बढ़ाने हेतु क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, नवाचार स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता पर कार्यशाला, लघु वनोपज के प्रसंस्करण एवं निर्यात पर संगोष्ठी, जैव विविधता संरक्षण एवं कृषक प्रजातियों के पंजीयन हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला, परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यताओं हेतु एनएबीएल द्वारा प्रशिक्षण, फसल प्रजनन आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण आदि प्रमुख हैं।
- कृषि मड़ई में फसलों की नई किस्में, अधिक आय देने वाली वैकल्पिक फसलें, नवीन कृषि प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक एवं जैविक कृषि, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक, पशु पालन, मछली पालन एवं चारा उत्पादन, समन्वित फसल पोषक तत्त्व तथा कीट एवं बीमारी प्रबंधन, मृदा उर्वरता एवं मृदा स्वास्थ्य, वर्षा जल प्रबंधन एवं भू-जल संवर्धन, संरक्षित खेती, उन्नतशील कृषि यंत्र प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन आदि के संबंध में विषय-विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी जाएगी। इस दौरान कृषि आधारित स्टार्टअप्स के सफल उद्यमियों द्वारा नवीन स्टार्टअप्स स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई में लगभग 20 हज़ार किसानों के शामिल होने की संभावना है।

नोट :

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सूचना आयोग के ऑनलाईन पोर्टल का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

12 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य सूचना आयोग कार्यालय में राज्य शासन के द्वारा तैयार किये गए राज्य सूचना आयोग के ऑनलाईन बेव पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा छठवाँ राज्य बन गया है, जहाँ ऑनलाईन की प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) में आवेदक आवेदन कर सकता है।
- मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस अवसर पर सुझाव देते हुए कहा कि ऑनलाईन बेव पोर्टल को हिन्दी में बनाया जाए ताकि जो लोग कंप्यूटर के मामले में कम शिक्षित हैं उन्हें इसका उपयोग करने में आसानी हो एवं जिसका लाभ आम नागरिकों को अधिक से अधिक मिल सके।
- उन्होंने सुझाव दिया कि सूचना का अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिये जनसंपर्क विभाग और आयोग मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडियो बनाकर ऑनलाईन वेब पोर्टल की पूरी प्रक्रिया को बताया जाना चाहिये, जिससे आम नागरिक इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।
- उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कॉलेज स्तर पर और राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के माध्यम से भी सूचना का अधिकार के ऑनलाईन बेवपोर्टल का हिन्दी में प्रचार-प्रसार कराया जाए तो ज्यादा लाभकारी होगा।
- मुख्य सूचना आयुक्त एम. के. राउत ने कहा कि यह ऑनलाईन बेव पोर्टल 24×7 दिन चालू रहेगा। आवेदक, जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को ऑनलाईन प्रेषित कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित शुल्क भी ऑनलाईन जमा कर सकते हैं।
- मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में लगभग 14 हज़ार से अधिक जनसूचना अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाईन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर संबंधितों को अग्रेषित कर सकते हैं। संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को इसका वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा।
- एम. के. राउत ने बताया कि राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। आवेदक अपना आवेदन ऑनलाईन अपलोड करने के साथ-साथ ऑनलाईन शुल्क जमा कर सकता है। आवेदकों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही विभागीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने अथवा डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
- उन्होंने कहा कि पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन पंजीयन होने के बाद जनसूचना अधिकारी की जवाबदेही बढ़ जाएगी और 30 दिवस के भीतर ही आवेदक को ऑनलाईन जानकारी देने के लिये बाध्य होगा।

छत्तीसगढ़ में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

14 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में विगत तीन वर्षों में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज करते हुए 7 हज़ार 217 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है।

प्रमुख बिंदु

- इनमें राज्य को कोयला खनन से प्राप्त राजस्व वर्षवार 2019-20 में 2 हज़ार 337 करोड़ रुपए, 2020-21 में 2 हज़ार 356 करोड़ रुपए तथा 2021-22 में 2 हज़ार 524 करोड़ रुपए है। यह उपलब्धि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ खनिज भंडारण नियम 2009 के कुशल क्रियान्वयन से हासिल हुई है।

नोट :

- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ खनिज भंडारण नियम, 2009 के तहत विशेष परिस्थिति में खनिज पट्टेधारियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों को खनिज प्रेषण पूर्व ज़िला कार्यालय को प्रस्तावित खनिज की मात्रा, ग्रेड प्राप्तकर्त्ता इत्यादि विषयक जानकारी दिये जाने के प्रावधान हैं।
- प्रदेश में कोयला खदानों का संचालन एवं प्रेषण प्रमुख रूप से भारत सरकार के उपक्रम एसईसीएल द्वारा किया जाता है। एसईसीएल द्वारा विभिन्न स्कीम, यथा-लिंकेज, ई-ऑक्शन आदि के माध्यम से पावर एवं नॉनपावर श्रेणी के अनुसार विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयला प्रदान किया जाता है।
- कोयले पर राज्य शासन को देय रॉयल्टी एसईसीएल द्वारा स्कीम अनुसार प्रदान किये जा रहे कोयले के बेसिक सेल प्राईस का 14 प्रतिशत होती है। स्कीमवाईज पावर एवं नॉन-पावर श्रेणी एवं ग्रेडवाईस कोयले के बेसिक सेल प्राईस में व्यापक अंतर होता है।

'नदी तट वृक्षारोपण' कार्यक्रम के तहत 26 नदियों के तट पर लगाए गए 15 लाख से अधिक पौधे

चर्चा में क्यों ?

16 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान 'नदी तट वृक्षारोपण' कार्यक्रम के तहत 26 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 15 लाख 41 हज़ार पौधों का रोपण किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- संजय शुक्ला ने बताया कि इन पौधों के रोपण से नदी तट का 1 हज़ार 400 हेक्टेयर रकबा हरीतिमा से आच्छादित और फल-फूल के पौधों से सुरभित होंगा, जो विशेष आकर्षण का केंद्र होगा।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा नदी तट रोपण का कार्य किया गया। इनका रोपण कैम्पा तथा विभागीय मद सहित 'नदी तट वृक्षारोपण'कार्यक्रम के तहत किया गया है।
- नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष के दौरान शामिल नदियों में शिवनाथ, फुलकदेई, केंदई, लीलागर, महानदी, हसदेव, आगर, रेड, मेघानाला, झींका, मोरन, सोंढूर, बांकी, गलफुला, हसदो, नेउर, केवई, खटम्बर, भैसुन, चूंदी, भवई, बनास, रांपा तथा भुलू नदी शामिल हैं।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि इनमें से बिलासपुर वृत्त के अंतर्गत बिलासपुर, मरवाही, कोरबा, धरमजयगढ़ तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल स्थित 8 नदियों के 263 हेक्टेयर रकबा में 2 लाख 89 हज़ार पौधों का रोपण किया गया है।
- इसी तरह कांकेर वृत्त के अंतर्गत 4 नदियों के 19 हेक्टेयर रकबा में 20 हज़ार 595 पौधे तथा रायपुर वृत्त के अंतर्गत 2 नदियों के 29 हेक्टेयर रकबा में 31 हज़ार 900 पौधों का रोपण किया गया है। इसके अलावा सरगुजा वृत्त के अंतर्गत सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया तथा मनेंद्रगढ़ वन मंडल स्थित 12 नदियों के 1 हज़ार 76 हेक्टेयर रकबा में 11 लाख 84 हज़ार पौधों का रोपण किया गया है।

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नवगठित ज़िला सक्ती में मुख्यमंत्री की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

18 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नवगठित ज़िला सक्ती के मालखरौदा, डभरा और चंद्रपुर विकासखंड में कई घोषणाएँ कीं।

प्रमुख बिंदु

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय मुकुटधर पांडेय स्मृति समिति की मांग पर चंद्रपुर के कॉलेज का नामकरण मुकुटधर पांडेय के नाम पर करने की बात कही और पुस्तकालय की मांग पर सहमति जताते हुए डभरा में सब्जी मंडी खोलने की घोषणा की।

विकासखंड- मालखरौदा में मुख्यमंत्री की घोषणा

- ग्राम पंचायत सिघरा में महिलाओं के प्रशिक्षण के लिये एन.आर.एल.एम. डोम निर्माण कार्य की घोषणा।
- ग्राम पंचायत सारसडोल में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को नवीन हाई स्कूल में उन्नयन की घोषणा तथा ग्राम मुक्ता में नवीन हाई स्कूल की घोषणा।

नोट :

- ग्राम जमगहन व सुलौनी में शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन की घोषणा।
- नगर पंचायत अडभार में माँ अष्टभुजी देवी की नगरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा।
- मालखरौदा में युवा प्रशिक्षण केंद्र में अहाता निर्माण की घोषणा।

विकासखंड - डभरा में मुख्यमंत्री की घोषणा

- साराडीह बैराज में पर्यटन स्थल का होगा विकास।
- चंद्रपुर में पर्यटन स्थल का विकास मरीन ड्राइव का निर्माण।
- ग्राम टूंड्री में पुलिस चौकी निर्माण और चंद्रपुर में नया थाना भवन निर्माण की घोषणा।
- ग्राम सिरियागढ़ के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाएगा।
- सकराली में नेगा 33/11 केवी सब स्टेशन।
- डभरा में सब्जी मंडी खोलने की घोषणा।

पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों में पी.पी.पी. मॉडल से संचालित होंगे कॉलेज

चर्चा में क्यों ?

18 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के पिछड़े, अति पिछड़े और सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों में अब पी.पी.पी. मॉडल में कॉलेजों का संचालन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पी.पी.पी. मॉडल पर प्रारंभ किये जाने वाले महाविद्यालय प्रदेश के लिये एक नवाचार है। प्रस्तावित पी.पी.पी. मॉडल में यह व्यवस्था प्रारंभ से ही निजी महाविद्यालयों को दी जाएगी। पूर्व में इस प्रकार की कोई योजना लागू नहीं की गई है और न ही कोई निजी महाविद्यालय इस योजना में दी गई व्यवस्था के तहत संचालित हो रहे हैं।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्रदेश में कुल 12 निजी महाविद्यालयों को शत्-प्रतिशत् नियमित अनुदान के तहत संचालित किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् चार निजी महाविद्यालयों को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के तहत कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत तीन वर्ष में एक बार तदर्थ अनुदान अधिकतम पाँच लाख रुपए तक भवन विस्तार, फर्नीचर, उपकरण क्रय के लिये दिया जा सकता है। आवेदन के आधार पर अनुदान की स्वीकृति दी जाती है।
- अब तक छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के आधार पर उपर्युक्त अनुदान केवल उन्हीं निजी महाविद्यालयों को प्रदान किया जाता है, जिनका संचालन न्यूनतम 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है, लेकिन प्रस्तावित पी.पी.पी. मॉडल में यह व्यवस्था प्रारंभ से ही निजी महाविद्यालयों को दी जाएगी। इससे अति पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रतिकूल स्थिति से उभरने के लिये तथा उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास में पी.पी.पी. मॉडल का क्रियान्वयन करने के लिये इस मॉडल को प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का विज़न है कि दुर्गम क्षेत्रों में भी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सकल प्रवेश अनुपात को बढ़ाने और राज्य के पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तामूलक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पी.पी.पी. मॉडल के तहत राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के प्रस्तावित प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- इसमें निर्धारित प्रारूप के तहत निजी महाविद्यालयों को दी जाने वाली रियायतों में पी.पी.पी. मॉडल के तहत खोले जाने वाले महाविद्यालयों को दी जाने वाली निश्चित पूंजी निवेश पर अधिकतम सब्सिडी 2.50 करोड़ रुपए एवं 1.75 करोड़ रुपए सब्सिडी क्रमशः अति पिछड़ा क्षेत्र एवं पिछड़ा क्षेत्र में स्थापित महाविद्यालयों को दी जाएगी।

नोट :

- इसी तरह कम-से-कम 10 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज़ पर 50 प्रतिशत रियायती दर से शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाएगा। लीज़ की अवधि की समाप्ति होने पर दोनों पक्षों की सहमति से लीज़ की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- अधोसंरचना निर्माण के लिये लिये गए अधिकतम 500 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा। समस्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को राज्य शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय को समस्त शैक्षणिक स्टाफ एवं कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था स्वयं के द्वारा करनी होगी। राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन के लिये कुल स्थापना पर व्यय की अधिकतम राशि 2 करोड़ रुपए पर 20 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत व्यय भार क्रमश: पिछड़ा क्षेत्र एवं अति पिछड़ा क्षेत्र में स्थापित महाविद्यालय को स्थापना अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- वहीं NAAC द्वारा A++, A+ या A ग्रेड प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों को 1 लाख 51 हज़ार रुपए प्रोत्साहन राशि एवं प्रमाण-पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। पी.पी.पी. मॉडल के तहत खोली जाने वाली उच्च शिक्षण संस्थाओं को NAAC/NIRF गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये देय शुल्क की 50 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए (जो भी कम हो) राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
- प्रस्तावित योजना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सकल प्रवेश अनुपात (GER) की वृद्धि में सहायक होगी। साथ ही राज्य के पिछड़े क्षेत्र एवं अति पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तामूलक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस योजना को प्रदेश में लागू किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में नारायणपुर टॉप 5 आकांक्षी ज़िलों में शामिल

चर्चा में क्यों ?

18 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जन-संपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा देश भर के आकांक्षी ज़िलों के परफॉर्मेंस के आधार पर अगस्त 2022 में जारी की गई रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष पाँच ज़िलों में अपना स्थान बनाया है।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी ज़िलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी ज़िला नारायणपुर पाँचवें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर ज़िले का स्थान दूसरा है। इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर ज़िला चौथे स्थान पर है।
- उल्लेखनीय है कि वंचित वर्ग के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके और वे भविष्य के अवसरों के लिये तैयार हो सकें, इसी संकल्पना को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल शुरू किये गए हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल के शुरू होने के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी अब अंग्रेज़ी माध्यम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।
- अंग्रेज़ी माध्यम के साथ ही हिन्दी माध्यम में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल भी शुरू किये गए हैं। इसके अलावा आकांक्षी ज़िलों में संचालित प्राथमिक स्कूल के बच्चों को उनकी स्थानीय बोली में भी शिक्षा दी जा रही है, जिससे वो अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ कर विषयों को आसानी से समझ रहे हैं।
- मुख्यमंत्री ने बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिये प्रदेशव्यापी 'मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान'शुरू किया है। इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। प्रदेश के लगभग 50 प्रतिशत कुपोषित बच्चे कुपोषणमुक्त हो चुके हैं। लगभग 2 लाख 11 हज़ार बच्चे कुपोषण के चक्र से बाहर आ गए हैं। इसके साथ ही 85 हज़ार महिलाएँ एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं।
- नागरिकों को सुलभ सुविधाएँ पहुँचाने के लिये 'मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक', 'दाई-दीदी क्लिनिक', 'मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना', 'हमर लैब', 'मलेरिया मुक्त बस्तर'और 'मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ योजना'के साथ 'डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना', 'मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना'संचालित की जा रही हैं।

नोट :

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

19 अक्टूबर, 2022 को भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत आर्थिक फसल बीमा पोर्टलों का डिजिटली एकीकरण डिजिटल भू-अभिलेख डाटाबेस (भुइयाँ) में करने के लिये छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 19 एवं 20 अक्टूबर, 2022 को केरल के कोच्चि में आठवें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन के पहले दिन छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया।
- यह पुरस्कार भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण छत्तीसगढ़ के डिजिटल भू-अभिलेख डाटाबेस 'भुइयाँ' में सीमित समय में सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर दिया गया है।
- छत्तीसगढ़ की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार को विशेष सचिव एवं संचालक कृषि छत्तीसगढ़ शासन डॉ. अबयाज फकीर तम्बोली तथा संयुक्त संचालक कृषि, संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ श्री बी.के. मिश्रा ने ग्रहण किया।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अनेक क्षेत्रों में नवाचार किये जा रहे हैं। वहीं हितग्राहियों को त्वरित लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, जिनमें से योजनाओं का डिजिटलीकरण मुख्य रूप से शामिल है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण प्रदेश के डिजिटल भू-अभिलेख डाटाबेस (भुइयाँ) से होने से कृषकों की भूमि विवरण संबंधित जानकारी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में भुइयाँ पोर्टल से सत्यापन उपरांत ही इंद्राज की जा सकेगी। इससे कृषकों के सही खसरा नंबर रकबा तथा सही ग्राम की जानकारी पोर्टल पर इंद्राज होने से फसल बीमा आवरण तथा दावा भुगतान की कार्यवाही सुगमतापूर्वक पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित होगी।

इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ को किया गया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

20 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के राजकोट में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आयोजित इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में 'प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021' के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को दो पुरस्कार प्राप्त हुये हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में हो रहे कार्यों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि व कृषक कल्याण, अधोसंरचना समेत हर क्षेत्र में निरंतर विकास की गति आगे बढ़ाने के परिणामस्वरूप राज्य ने एक बार फिर देश में अपना परचम लहराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के अंतर्गत दो पुरस्कार प्राप्त किये हैं।
- छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में मिला है।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में 'मोर जमीन-मोर मकान' योजना शुरू की गई, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जोड़ते हुए नगर पालिका निगम राजनांदगाँव के आशा नगर में निवासरत कुष्ठ रोग से ग्रसित परिवारों को अन्य 19 केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ अभिसरण करते हुए 61 परिवारों को सर्वसुविधायुक्त पक्का आवास दिया गया। इससे उनकी जीवनशैली में सुधार आया।
- इसी तरह नगर पंचायत गंडई एवं अंतागढ़ में भी विशेष वर्ग के हितग्राहियों को भी सर्वसुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया गया और उनकी जीवनशैली में सुधार लाने का प्रयास किया गया।
- छत्तीसगढ़ में सामाजिक उत्थान को लेकर हुए इन प्रयासों को सराहते हुए सामाजिक उत्थान परियोजनाओं के लिये छत्तीसगढ़ राज्य को 'बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स'की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

नोट :

- इसके अलावा नगर पंचायत पाटन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 'मोर जमीन-मोर मकान' योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरुद्ध अधिक संख्या में आवास पूर्ण कर हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने एवं आकर्षक आवास बनाने जैसे उत्कृष्ट कार्य के लिये 'बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत'श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं राज्य में जनकल्याणकारी नीतियों के लिये भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को पिछले पौने चार साल में अनेक पुरस्कार प्रदान किये जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में होगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव

चर्चा में क्यों ?

21 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में नौ देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार भाग लेंगे।
- इस महोत्सव के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कलाकारों के बीच उनकी कलाओं की साझेदारी होगी, बल्कि वे एक-दूसरे के खान-पान, रीति-रिवाज, शिल्प-शैली को भी देख-समझ सकेंगे।
- उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के क्रम में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के रूप में एक महत्त्वपूर्ण परंपरा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। प्रदेश का यह प्रयास न केवल छत्तीसगढ़ के लिये, बल्कि देश और पूरी दुनिया के जनजातीय समुदायों के विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वनवासियों, आदिवासियों, किसानों, ग्रामीणों और वंचित वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण में कला, संस्कृति और पर्यटन को राज्य सरकार ने एक मज़बूत संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किया है और इसके बढ़िया परिणाम भी मिले हैं।
- छत्तीसगढ़ की ओर से नौ देशों को आमंत्रण-पत्र भेजा गया है। ये सभी देश पहली बार रायपुर में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन में मोजांबिक, मंगोलिया, टोगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूज़ीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे।
- दिल्ली पहुँचने वाले विदेशी मेहमानों को छत्तीसगढ़ तक लाने-ले जाने और उनकी मेहमान-नवाज़ी में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, दिल्ली (आई.सी.सी.आर) सहयोगी होगी।
- इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में दो थीम रखी गई हैं। पहली थीम है- 'फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य'और दूसरी थीम है- 'आदिवासी परंपराएँ और रीति-रिवाज'।
- विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। प्रथम स्थान के लिये 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिये 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान के लिये 2 लाख रुपए के पुरस्कार दिये जाएंगे।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मिला राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच सिल्वर अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

28 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित 'मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना'को गुणवत्तायुक्त एवं रोज़गार आधारित नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड-2022 से सम्मानित किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- देश में सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्य का गौरव हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर इस गौरवपूर्ण सम्मान से नवाजा गया है।
- छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा युवाओं को उनकी रुचि अनुसार गुणवतायुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पाकर युवा लगातार सरकारी और गैर-सरकारी विभागों में नौकरी पाने के साथ ही स्वरोज़गार को अपना रहे हैं।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख 68 हज़ार 184 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2 लाख 55 हज़ार 678 युवाओं को नियोजित किया गया है। वर्तमान में 2726 युवा प्रशिक्षणरत् हैं।

मुख्यमंत्री ने 28 ज़िलों में सिकलसेल प्रबंधन केंद्रों का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

30 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के 28 ज़िलों में सिकलसेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और ज़िला अस्पतालों में स्थापित नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन करते हुए छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकलसेल रिसर्च सेंटर की स्थापना किये जाने की घोषणा की।
- इसके साथ ही प्रदेश के 24 ज़िला अस्पतालों, नौ मेडिकल कॉलेजों तथा राजधानी रायपुर स्थित सिकलसेल संस्थान छत्तीसगढ़ में सिकलसेल की नि:शुल्क जाँच, उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध हो गई है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकलसेल की समस्या का प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह केंद्र प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज अस्पतालों एवं सभी ज़िला चिकित्सालयों में संचालित किये जाएंगे।
- इन केंद्रों में सिकलसेल की जाँच एवं उपचार के साथ अस्पताल की प्रयोगशाला के माध्यम से साल्युबिटी टेस्ट द्वारा स्क्रीनिंग एवं इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा नवीन विधि पॉइंट ऑफ केयर (POC) टेस्ट द्वारा पुष्टि हेतु जाँच उपलब्ध कराई जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकलसेल जाँच की नवीन विधि पॉइंट ऑफ केयर (POC) टेस्ट काफी आसान है। मितानिनें भी इस विधि से जाँच कर सकती हैं। इस पद्धति से अभियान चलाकर सिकलसेल मरीज़ों की पहचान की जा सकती है।
- मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में सिकलसेल से पीड़ित राजेंद्र नगर रायपुर के सातवर्षीय बालक प्रतिक दास मानिकपुरी और गुढ़ियारी की 17 वर्षीय बालिका ओशिका रामटेके को डिजिटल कार्ड प्रदान कर सिकलसेल से पीड़ित व्यक्तियों को डिजिटल कार्ड वितरण का शुभारंभ किया।
- स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. ने कार्यक्रम में बताया कि अब तक किये गए सर्वे में प्रदेश की दस प्रतिशत आबादी में सिकलसेल वाहक और एक प्रतिशत रोगी पाए गए हैं। सिकलसेल प्रबंधन केंद्रों में विशेष रूप से उपचार प्राप्त कर रहे प्रत्येक सिकलसेल रोगी की इलेक्ट्रॉनिक एंट्री सिकलसेल संस्थान के पोर्टल में कर सूची संधारित की जाएगी एवं उन्हें नियमित फॉलो-अप एवं दवा लेने हेतु संपर्क किया जाएगा।

समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की सहूलियत के लिये एन्ड्रॉयड ऐप 'टोकन तुंहर हाथ

चर्चा में क्यों ?

29 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पंजीकृत किसान को धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से एन.आई.सी. द्वारा एन्ड्रॉयड ऐप 'टोकन तुंहर हाथ'विकसित किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 'टोकन तुंहर हाथ'ऐप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केंद्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप के उपयोग से पंजीकृत किसानों द्वारा संबंधित समिति उपार्जन या उपार्जन कंद्रों में आगामी 7 दिवस तक टोकन प्राप्त किया जा सकता है।
- इस ऐप द्वारा किसान को समिति द्वारा दर्ज किसान की जानकारी पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन एवं धान खरीदी आदि की सभी नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त होंगी।
- ऐप के माध्यम से संबंधित समिति या उपार्जन केंद्र में प्रत्येक दिन की खरीदी क्षमता के 30 प्रतिशत की सीमा तक ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त सीमा में भी सीमांत, लघु व दीर्घ कृषकों को उनकी पंजीकृत संख्या के अनुपात में टोकन हेतु समान अवसर उपलब्ध होगा।
- संबंधित समिति उपार्जन केंद्र में शेष 70 प्रतिशत खरीदी क्षमता की मात्रा ऑफलाइन टोकन हेतु उपलब्ध रहेंगी, ताकि जो किसान ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करने में असुविधा महसूस करते हैं, उन्हें पूर्व वर्षों की भाँति समिति मॉड्यूल से टोकन प्राप्त हो सके।
- ऐप के माध्यम से टोकन जारी करने की व्यवस्था पूर्व वर्षों में समिति माड्यूल से टोकन जारी करने की व्यवस्था करने की प्रक्रिया के अलावा अतिरिक्त रूप से की जा रही है। इस प्रकार कृषकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से टोकन प्राप्त हो सकेगा।
- उक्त ऐप के उपयोग से निम्नलिखित लाभ संभावित हैं-
  - समिति/उपार्जन केंद्रों में टोकन प्राप्त करने हेतु किसानों की भीड़ में कमी आएगी।
  - किसानों को घर-बैठे धान बेचने हेतु टोकन प्राप्त हो सकेगा, उन्हें समिति, उपार्जन कंद्रों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - किसानों को अपनी पंजीयन संबंधित जानकारी, जैसे- व्यक्तिगत, भूमिगत/खाता/धान खरीदी एवं भुगतान की जानकारी भी सुगमता से प्राप्त हो सकेगी।

The Vision

नोट :